



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 51] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 18, 1971 (अग्रहायण 27, 1893)
No. 51] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 18, 1971 (AGRAHAYANA 27, 1893)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to 8th February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazette Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines Delhi. Indents should be submitted so as to reach the manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

M371G1/71

(1041)

विषय-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	पृष्ठ 1041	भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	पृष्ठ 6717
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1821	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	1051
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	121	भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	1687
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1471	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें	459
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	185
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	2611
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	5263	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	241
		पूरक संख्या 51—	
		11 विसम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्टें	2139
		20 नवम्बर 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	2149

CONTENTS

PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	PAGE 1041	PART II—SECTION 3.—Sub-Sec. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	PAGE 6717
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1821	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	1051
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	121	PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	1687
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1471	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	459
PART II—SECTION 1.—Arts, Ordinances and Regulations	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	185
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2611
PART II—SECTION 3.—Sub-Sec. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).	5263	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	241
		SUPPLEMENT NO. 51—	
		Weekly Epidemiological Reports for week ending 11th December 1971	2139
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week end 20th November 1971	2149

भाग I—अध्याय 1

(PART I—SECTION 1)

रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1971

सं० एफ० 3(83)-एन० एस०/68—राष्ट्रपति एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की 19 दिसम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या एफ० 3(40)-एन० एस०/58 के साथ प्रकाशित डाकघर बचत बैंक (संचयी सावधि जमा) नियमावली, 1958 में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों को डाकघर बचत बैंक (संचयी सावधि जमा)—संशोधन नियमावली, 1971 कहा जायेगा।

(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. डाकघर बचत बैंक (संचयी सावधि जमा) नियमावली, 1958 के नियम 11 का उप-नियम ग (ii) को संशोधित करके निम्नलिखित प्रकार से पढ़ा जाए:—

“(ii) जहां वापसी अदायगी किस्तों में की जानी हो उस मामले में, वापसी अदायगी की अवधि के अन्त में उस रकम पर 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लगाया जाएगा जो उस महीने से लेकर, जिसमें रकम निकाली गयी थी, प्रत्येक महीने के अन्त में अदत्त रही हो, और ब्याज की रकम एक ही किस्त में वसूल की जाएगी यह ब्याज की किस्त या तो वापसी अदायगी की आखिरी किस्त के साथ वसूल की जाएगी या उस महीने के बाद के महीने में जिसमें आखिरी किस्त की वापसी अदायगी की गयी हो।

ए० बी० श्रीनिवासन, अवर सचिव

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 नवम्बर 1971

संकल्प

सं० 11(2)/71/ई०ई० आई०—भारत सरकार ने इस्पात की गड़ी हुई वस्तु उद्योग के विकास से संबंधित विभिन्न मामलों की जांच करने के उद्देश्य से संकल्प सं० 11(1)/67-ई० आई० (एम०) दिनांक 1 फरवरी, 1969 के द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिये इस्पात की गड़ी हुई वस्तु उद्योग की नामिका का गठन किया था। नामिका का विगत कार्यकाल 31 जुलाई, 1971 को पहले ही समाप्त हो गया है और अब इस्पात की

गड़ी हुई वस्तु उद्योग की नामिका का पुनर्गठन करने का निश्चय किया गया है।

2. नामिका के विचारार्थ विषय ये हैं:—

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के लिये किस्मवार, प्रकारवार, विशिष्टीकरण मांग का निर्धारण करना,

(ख) जिन एककों में पहले से उत्पादन हो रहा है उनकी क्षमता की समीक्षा करना, यदि कोई अंतर हो तो उसे पूरा करना,

(ग) उत्पादन में वृद्धि करके अथवा नये उत्पादन का विकास करके विद्यमान एककों में विविधीकरण करना,

(घ) उपर्युक्त (ख) तथा (ग) में उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दी जाने वाली सहायता,

(ङ) कच्चा माल, पुर्जों आदि के रख-रखाव के बारे में समस्याएँ यदि कोई हों,

(च) इस उद्योग के लिये ऐसी उत्पादन मशीनों तथा उपकरणों का विकास करना, जिनका विकास अब तक नहीं किया गया है, विदेशों मुद्रा पर निर्भरता का कम करना, और

(छ) समय-समय पर आनेवाले अन्य सम्बन्धित मामले।

3. नामिका में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

अध्यक्ष

(1) श्री एन० जे० कामत, संयुक्त सचिव,
औद्योगिक विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

सदस्य-गण

(2) श्री बी० पी० सोनी, संयुक्त निदेशक
(विकास) रेलवे स्टोर, रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड) नई दिल्ली।

(3) श्री पी० आर० लेटी, प्रमुख (इंजीनियरी)
(उद्योग तथा खनिज प्रभाग)
योजना आयोग, नई दिल्ली।

(4) डा० ए० के० डे०, निदेशक, केन्द्रीय
मानिक इंजीनियरी, अनुसंधान
संस्थान, महात्मा गांधी एवेन्यु,
दुर्गापुर-9।

- (5) श्री जे० एन० लूथरा, तकनीकी सेवा प्रमुख, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लि०, चाणक्य भवन, नई दिल्ली नगर निगम कम्प्लेक्स, विनय मार्ग, नई दिल्ली।

- (6) श्री के० पी० टंडन, प्रमुख अधीक्षक (गढ़ाई शाला) हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि० फाउंड्री फोर्ज, ब्रकखाना—रांची-4।

- (7) श्री डी० आर० मलिक, महाप्रबंधक, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, रामीपुर (हरद्वार) उ० प्र०।

- (8) श्री एन० सेन राय, प्रमुख योजना अधिकारी, संयुक्त प्लांट समिति, 18, रबीन्द्र सरणी, कलकत्ता-1।

- (9) श्री आर० एन० दत्त, महाप्रबंधक, आइर्नेम्स फ़ैक्ट्री, भुसावल, रक्षा मंत्रालय (उत्पादन)।

- (10) श्री पी० बी० जयकुमार, विपणन निदेशक (इंजी) तथा (गढ़ाई) डिबीजन, मे० गेस्ट, कीम, विलियम्स लि०, जीवन बीप, 1, मिडिलटन स्ट्रीट, कलकत्ता-16।

- (11) श्री एन० ए० कल्याणी, निदेशक, मे० भारत फोर्ज कं० लि०, मुडवा पूना-1।

- (12) श्री डी० आर० शारदा, प्रबंधक पार्टनर, मे० नेशनल स्टील एण्ड जनरल मिल्स, पटेल मार्ग, गाजियाबाद (उ० प्र०)।

सबस्थ-सचिव

- (13) श्री वी० वी० वीरभद्रैया, विकास अधिकारी, तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली।

4. इस सलाहकार नामिका की बैठक अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये गये स्थान पर छः महीने में एक बार या आवश्यक-तानुसार उससे अधिक, स्थिति की समीक्षा करने के लिये होगी। यह अपने द्वारा देखे गये प्रकरणों का प्रतिवेदन समय-समय पर भारत सरकार को प्रस्तुत करेगी।

5. नामिका का कार्यकाल इस संकल्प के जारी होने की तिथि से दो वर्षों का होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को एक-एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाए और सर्वसारधारण की जानकारी के लिये इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

आर० सी० सेठी, उप सचिव

कम्पनी कार्य विभाग

(कम्पनी विधि बोर्ड)

नई दिल्ली 1, दिनांक 1 दिसम्बर 1971

आदेश

सं० 53/1/70-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 की 1) की धारा 209 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (2) के अन्तर्गत, कम्पनी, विधि बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के एक अधिकारी श्री सूरज कपूर, लेखाधिकारी को कथित धारा 209 के उद्देश्य के लिए अधिकार देता है।

औद्योगिक विकास आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय, कम्पनी कार्य विभाग के आदेश संख्या 51/1/65-सी० एल०-2 दिनांक 18 जुलाई, 1969 को श्री सूरज कपूर के पक्ष में प्रेषित अधिकार को कम्पनी विधि बोर्ड एतद्वारा निरस्त करता है।

के० बी० घोष, अवर सचिव
कम्पनी विधि बोर्ड

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(परिवार नियोजन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 1971

संकल्प

सं० 2-11/71-नीति—केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद् ने अक्टूबर, 1971 में जयपुर में हुई अपनी बैठक में सिफारिश की थी कि परिषद् की बैठकों के अन्तर्काल में परिवार नियोजन कार्यक्रम में समय-समय पर उठने वाले विभिन्न मामलों को निपटाने के लिये एक कार्यकारणी समिति का गठन किया जाए। भारत सरकार ने यह सिफारिश मान ली है तथा यह निश्चित किया है कि परिषद् की एक कार्यकारणी समिति गठित की जाये जिसका गठन इस प्रकार होगा:—

अध्यक्ष

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री।

उपाध्यक्ष

(बाइस चेयरमैन)

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार नियोजन राज्य मंत्री।

उपाध्यक्ष

(ट्रिपटी चेयरमैन)

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन उप-मंत्री

सबस्थ-गण

स्वास्थ्य मंत्री, उड़ीसा

स्वास्थ्य मंत्री, महाराष्ट्र

स्वास्थ्य मंत्री, तमिलनाडु

स्वास्थ्य राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश

संयोजक

सदस्य सचिव, केन्द्रीय परिवार नियोजन परिषद्।

2. कार्यकारिणी समिति के कार्य वे होंगे जो उसे अध्यक्ष द्वारा समय समय पर सौंपे जायेंगे तथा वह परिषद् सम्बन्धी सभी बातों में अध्यक्ष की सहायता करेगी।

3. कार्यकारिणी समिति की बैठकों का समय और स्थान अध्यक्ष द्वारा समय समय पर निश्चित किया जायेगा।

4. इस समिति का कार्यकाल वर्तमान परिषद् के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगा।

आदेश

आदेश है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि आम सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दी जाए।

दिनांक 2 दिसम्बर 1971

सं० 17-15/71-ए० पी० (सीति)—प्रजनन जीव विज्ञान, जनांकिकी तथा संचार कार्य के क्षेत्र में अनुसंधान के तालमेल के लिये भारत सरकार ने एक "परिवार नियोजन अनुसंधान समन्वय समिति" का गठन किया है।

2. इस समिति का गठन इस प्रकार होगा :

अध्यक्ष

1. सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय।

सदस्य-गण

2. संयुक्त सचिव, परिवार नियोजन

3. स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक

4. भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् के महानिदेशक।

5. आयुक्त, परिवार नियोजन

6. निदेशक, राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली।

7. डा० एम० के० कृष्णमैनन स्त्रीरोग विद्, मद्रास।

8. डा० एम० आर० एन० प्रसाद, जीव विज्ञान, विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

9. डा० बी० रामालिंगस्वामी, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

10. डा० एम० एस० धर, निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ।

11. डा० डी० एन० पै, निवारक तथा सामाजिक चिकित्सा विभाग टोपी-वाला राष्ट्रीय चिकित्सा कालेज, अम्बई।

सदस्य सचिव

2. उप-आयुक्त (प्रशिक्षण एवं अनुसंधान) परिवार नियोजन विभाग, नई दिल्ली।

3. इस समिति के निर्देश-पद इस प्रकार होंगे:—

(1) लक्ष्यों का निर्धारण तथा पुनर्जनन जीव विज्ञान, जनांकिकी तथा परिवार नियोजन सम्बन्धी संचार कार्य के अनुसंधान के लक्ष्य निर्धारित करना तथा प्राथमिकताएं सुझाना;

(2) उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान गतिविधियों में तालमेल रखना;

(3) अनुसंधान के क्षेत्रों का निर्धारण करना तथा उन संस्थाओं का अनुमोदन करना जहां अनुसंधान कार्य आरम्भ किये जाने चाहिए, तथा

(4) समय समय पर अनुसंधान की प्रगति का मूल्यांकन करना।

4. यदि समिति आवश्यक समझे तो उसे अपनी बैठकों में भाग लेने के लिये अन्य विशेषज्ञों को सहयोजित/आमंत्रित करने तथा उपसमितियां गठित करने की शक्ति होगी। इस समिति की बैठकें आवश्यकतानुसार बुलाई जाएंगी। आमतौर पर इस समिति की बैठकें नई दिल्ली में होंगी।

5. इस समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

6. इस समिति के गैर सरकारी सदस्य तथा इसमें आमंत्रित व्यक्ति समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये उन्हीं दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ता लेने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सेवाओं की प्रथम श्रेणी के उच्चतम ग्रेड के किसी अधिकारी को लागू होती हैं। समिति के उन सदस्यों को जो सरकारी कर्मचारी हैं, प्राप्य दरों पर यात्रा और दैनिक भत्ते उसी स्रोत से प्राप्त होंगे जहां से उन्हें वेतन मिलता है।

7. इस पर होने वाला खर्च मुख्य शीर्ष 30-ए० परिवार नियोजन सी०-1-तकनीकी सलाह और पर्यवेक्षण मांग संख्या 37 चिकित्सा और जनस्वास्थ्य वर्ष 1971-72 के अन्तर्गत स्वीकृत बजट अनुदान में से किया जाएगा।

आदेश

आदेश है कि आम सूचना के लिये यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

रवीन्द्रनाथ मधोक, संयुक्त सचिव

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

पर्यटन विभाग

नई दिल्ली 1, दिनांक 30 नवम्बर 1971

संकल्प

सं० 5 टी० कोआई० (4)/70—भारत सरकार, पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय, पर्यटन विभाग, में पर्यटक विकास परिषद् के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

भारत सरकार, परिवहन और संचार मंत्रालय, परिवहन विभाग के संकल्प सं० 3-टी० टी० (14)/67 दिनांक 27 फरवरी, 1958, जिसे भारत सरकार के सम-संख्यक संकल्प

दिनांक 23 अप्रैल, 1958; 24 जुलाई, 1958 और 26 दिसम्बर, 1958 तथा सं० 3-टी० पी० एल० 11(7)/62 दिनांक 31 जुलाई, 1962 और सं० 8टी० एम० (3)/64 दिनांक 25 जून, 1964; सं० 13 टी० पी० एल० 1(5)/64, दिनांक 2 अगस्त, 1965, सं० 13 टी० पी० एल० 1(5)/64, दिनांक 10 जून, 1966 और पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय, पर्यटन विभाग के संकल्प सं० 13-टी० पी० एल० 1(2)/67, दिनांक 7 जून, 1967; सं० 13-टी० पी० एल० 1(2)/67, दिनांक 3 जुलाई, 1968 और सं० 13-टी० पी० एल० 1(2)/67 दिनांक 13 अगस्त, 1968 द्वारा यथा-संशोधित किया गया, के मौजूदा भाग II को संशोधित किया जाना है, अतः उसे निम्नलिखित रूप से पढ़ा जाए :—

III परिषद् (काउंसिल) का गठन

परिषद् का गठन निम्नलिखित होगा :—

अध्यक्ष

1. मंत्री, पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय, केन्द्रीय सरकार।

उपाध्यक्ष

2. राज्य मंत्री, पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय केन्द्रीय सरकार।

सदस्य-गण

1. सदस्य (उद्योग), योजना आयोग।
2. प्रत्येक राज्य और गोवा संघ शासित क्षेत्र (19 राज्य, जिनमें मेघालय और संविधान सभा से युक्त एक संघ शासित प्रदेश, शामिल हैं) में पर्यटन विभाग के मंत्री।
3. मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली।
4. सचिव, पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय।
5. महानिदेशक, पर्यटन विभाग।
6. महानिदेशक, नागर विमानन विभाग।
7. महानिदेशक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण।
8. वन महानिरीक्षक (खाद्य तथा कृषि मंत्रालय)।
9. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग का एक प्रतिनिधि।
10. निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
11. रेल मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
12. परिवहन तथा जहाजरानी मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
13. एक संघ शासित क्षेत्र (स्थायी प्रतिनिधित्व नहीं है) का पर्यटन कार्यभार संभालने वाला मंत्री/मुख्य सचिव।
14. नो (9) संसद सदस्य। वे भारत सरकार के पर्यटन से सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा नामांकित किए जाएंगे।
15. भारत के होटल और रेस्टोरेंट संघ का एक प्रतिनिधि।

16. भारत के यात्रा अभिकर्ताओं के संघ का एक प्रतिनिधि।
17. भारत के शिकार साज-सामान आयोजक संघ का एक प्रतिनिधि।
18. एयर इंडिया का एक प्रतिनिधि।
19. इंडियन एयरलाइन्स का एक प्रतिनिधि।
20. भारत पर्यटन विकास निगम, लिमिटेड का एक प्रतिनिधि।
21. भारत की आटोमोबाइल संस्थाओं के संघ का एक प्रतिनिधि।
22. भारतीय वाणिज्य और उद्योग कैम्बर का एक प्रतिनिधि।
23. पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र से नामांकित नौ सदस्य।

सचिव :—केन्द्रीय सरकार द्वारा नामांकित एक अधिकारी परिषद् का सचिव होगा।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाए और आम जानकारी के लिए इसे भारत राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० एन० रामन, महानिदेशक,
पर्यटन एवं पदेन संयुक्त सचिव

सिचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 27 नवम्बर 1971

संकल्प

सं० 12(21)/70 सामग्री—भारत सरकार (सिचाई और विद्युत मंत्रालय) ने 8 जुलाई, 1969 को श्री कमलापति त्रिपाठी तत्कालीन उपमुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में मंत्रियों की एक समिति सिचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिये अपेक्षित निर्माण उपस्कर और फालतू पुर्जों की प्राप्ति में देरियों के कारणों का पता लगाने और इनकी प्राप्ति में देरियों को दूर करने हेतु उपाय सुझाने के लिये स्थापित की थी।

2. श्री कमलापति त्रिपाठी के उत्तर प्रदेश के उपमुख्य मंत्री के पद को त्याग देने पर प्रो० सिद्धेश्वर प्रसाद, केन्द्रीय सिचाई और विद्युत उपमंत्री को समिति की बैठकों का आयोजन करने के लिये अनुरोध किया गया था।

3. समिति ने अपनी रिपोर्ट 6 जुलाई, 1970 को भारत सरकार, सिचाई और विद्युत मंत्रालय को प्रस्तुत की थी। इस रिपोर्ट पर विचार किया गया और समिति की सिफारिशों को 24 और 25 सितम्बर, 1970 को उटकमंड में हुए राज्यों के सिचाई और विद्युत मंत्रियों के पांचवें सम्मेलन द्वारा स्वीकार कर लिया गया।

4. समिति की सिफारिशों और उन पर भारत सरकार के निर्णयों को उपासंध में दिया गया है।

5. समिति द्वारा किये गये मूल्यवान कार्य के लिये सरकार उसे प्रशंसा का पत्र समझती है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में सूचना के लिए प्रकाशित कर दिया जाए।

उपाबंध

क्रम सं०	समिति का सुझाव	सरकार का फैसला
1.	डी० जी० टी० डी० की स्वीकृति प्राप्त किए बिना निर्धारित सीमा तक पाबन्दी लगे फालतु पुजों का आयात करने के लिए आयात व्यापक नियंत्रण नीति में प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों को उपलब्ध रियायत सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं तथा राज्य विद्युत बोर्डों को भी मिलनी चाहिए।	स्वीकृत I नियमावली एवं प्रक्रिया की आयात व्यापार नियंत्रण पुस्तिका 1971 में पैरा 204 से आवश्यक उपबंध कर दिया गया है।
2.	उत्पादक मशीनरी के ब्रेकडाउन से बचने के लिए आपातकालीन पुजों के आयातार्थ आपातकालीन लाइसेंस सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को भी दिए जाने चाहिए। लाइसेंस अवधि में ऐसे लाइसेंसों का मूल्य प्रत्येक परियोजना के पास उपस्कर के मूल्य के 0.1% पर निर्धारित कर देना चाहिए।	स्वीकृत I प्रत्येक सिंचाई परियोजना/राज्य बिजली बोर्ड/विद्युत परियोजना/उपक्रम के पास पड़े उपस्कर की कीमत के 0.1% तक आपातकालीन लाइसेंस समय-समय पर सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा नोटिफाई होने वाली प्रत्येक परियोजना/बोर्ड के लिए सीमाओं के निर्धारण के अधीन दिए जाएंगे। आगे और सहायित के रूप में सिंचाई और विद्युत परियोजनाएं/विद्युत बोर्ड और उपक्रम आपातकालीन लाइसेंसों के लिए संबंधित क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकारियों के पास पहुंचेंगे।
3.	पाबन्दी लगे माल के लिए भारतीय व्यापार पत्रिका में कोई भी विज्ञापन नहीं दिया	स्वीकृत, वास्तविक उपभोक्ताओं के संबंध में। मूदवाही मशीनरी के लिए पुजों के प्रतिष्ठित आयातकों के लिए

क्रम सं०	समिति का सुझाव	सरकार का फैसला
	जाना चाहिए। उपस्कर की उन मदों के बारे में जिन पर पाबन्दी नहीं लगी, वास्तविक उपभोक्ताओं के मामले में विज्ञापन की इस शर्त को ढीला कर देना चाहिए।	विज्ञापन संबंधी प्रक्रिया जारी रहेगी।
4.	ऋणों/क्रेडिटों के अधीन सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए विदेशी मुद्रा देने के मामले में ऋणों की आखिरी तारीखें और डिलिवरी की अवधि विदेशी मुद्रा के अनुमोदन पत्रों में लिखी जानी चाहिए ताकि मुख्य नियंत्रक, निर्यात एवं आयात, बिना संबंधित विभागों से पत्र व्यवहार किए ही लाइसेंसों को पुनः सक्रिय कर सकें।	स्वीकृत I सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं और राज्य विद्युत बोर्डों/उपक्रमों को परियोजना ऋण के अधीन दी गई विदेशी मुद्रा संबंधी स्वीकृतियों में ऋण और डिलिवरी अवधियों की आखिरी तारीखें दी जाएंगी।
5.	फालतु पुजों और उपस्कर के आयात के लिए अध्यायनाओं पर कार्यवाही में प्रक्रियात्मक विलम्बों को न्यूनतम करने के लिए कार्यवाही को जानी चाहिए; प्रार्थना पत्रों के लिए नये फार्म बनाए जाने जिसमें विदेशी मुद्रा की स्वीकृति के और आयात लाइसेंस जारी होने के फार्म दोनों ही समा जाएं; आयात लाइसेंस प्रार्थना-पत्रों पर कार्यवाही करने की अवधि एक मास तक सीमित कर दी जाए।	स्वीकृत। विदेशी मुद्रा देने और पुजों के आयात के लिए आयात लाइसेंस देने के लिए एक सरल प्रक्रिया और संयुक्त फार्म को तैयार करके सिंचाई और विद्युत मंत्रालय द्वारा सभी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं/विद्युत बोर्डों और उपक्रम को परिपक्वित कर दिया गया है।

क्रम सं०	समिति का सुझाव	सरकार का फैसला	क्रम सं०	समिति का सुझाव	सरकार का फैसला
6.	पिछले दर ठेकों की स्वीकृत। मान्यता अवधि खत्म होने से पूर्व, फालतू पुर्जों के आयात के लिए डी० जी० एस० एण्ड डी० के दर ठेकों को काफी पहले अंतिम रूप दे देना चाहिए।		10.	उपयोग करने वालों के पास उन उपलब्ध फालतू पुर्जों की पूर्ति के लिए और जो पुर्जे उपयोग करने वालों के पास तत्काल उपलब्ध न हो सकते हों, उनके आयात के लिए उपस्कर के सतत-विक्रेताओं और फालतू पुर्जों के सुव्यवस्थित आयात कर्ताओं को विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में आवंटन किया जाए। वास्तविक उपभोक्ताओं की जरूरत की पूर्ति के लिए सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय को विदेशी मुद्रा का भारी मात्रा में आवंटन साथ-साथ जारी रखा जाना चाहिए।	
7.	देशी फालतू पुर्जों के लिए डी० जी० एस० एण्ड डी० को अधिक से अधिक मर्चे दर ठेकों के अन्तर्गत से लेनी चाहिए। डी० जी० एस० एण्ड डी० को देश में बने उपस्कर को भी, डी० जी० एस० एण्ड डी० के ठेकों के अन्तर्गत से लेना चाहिए।	स्वीकृत।			
8.	उपस्कर, पुर्जों और सहायक उपकरण के आयात के मामलों का पुनरवलोकन करने के लिए जिन पर विशेष रूप से विचार करने की आवश्यकताएं डी० जी० टी० डी० द्वारा एक समिति स्थापित की जाए। समिति को महीने में एक बार बैठक करनी चाहिए।	स्वीकृत। सिंचाई और विद्युत् परियोजनाओं/विद्युत् बोर्डों और उपक्रमों के उन अनर्णित मामलों का पुनरवलोकन करने के लिए डी० जी० टी० डी० में महीने में एक बैठक होगी जिनके लिए देशी स्वीकृति की आवश्यकता होगी।			
9.	तकनीकी विकास महा-निदेशालय को चाहिए कि जो फालतू पुर्जों और उपस्कर देश में बनाए जा रहे हैं, उनकी मर्चों की सूचियां तैयार करें और उन्हें प्रकाशित करें।	स्वीकृत।	11.	उपस्करों के उचित उपयोग, फालतू मशीनों को दूसरी जगह लगाने और फालतू पुर्जों की तालिका नियंत्रण के मामले में परियोजना अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए राज्य-स्तरीय पर केन्द्रीय मशीनी यूनिट संगठन का गठन और मौजूदा संगठनों का सुदृढ़ीकरण।	स्वीकृत। राज्य सरकारों से निवेदन किया गया है कि वे इन के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करें।
			12.	एक निर्माण संयंत्र तथा मशीनरी समिति का गठन किया जाए जो देश	स्वीकृत। देश में आयातित उपस्कर के इष्टतम उपयोग के संबंध में जांच करने और

श्रुत सं०	समिति का सुझाव	सरकार का फैसला
	में निर्माण उपस्कर की संख्या के बारे में सांख्यिकीय आंकड़े संकलित करे और जो उपस्कर की विभिन्न मदों की उत्पादन क्षमता, विभिन्न मशीनों के द्वारा कार्य-लागत इकाई और उपस्कर के मानकीकरण के बारे में मान-दंड निर्धारित करे। केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग के यांत्रिक संगठन को उचित रूप से सुदृढ़ बनाया जाए ताकि उपयुक्त स्तर का एक अधिकारी आवश्यक स्कीमों/उपायों को कारगर क्रियान्विति के लिए अंतिम रूप दे सके।	एक रिपोर्ट देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है।
13.	तकनीकी विकास महानिदेशालय, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग और सभरण और निपटान महानिदेशालय को आयात-प्रतिस्थापन में वृद्धि की सीमा देश में बनाए जाने वाले फालतू पुर्जों का उत्पादन और देश में बने उपस्कर और फालतू पुर्जों की मूल्य-संरचना की जांच करनी चाहिए।	स्वीकृत। इस मद पर कार्यवाही जारी रहेगी।
14.	मिट्टी हटाने वाली मशीनों आदि के फालतू पुर्जों के स्टार्कों के सख्त तालिका-नियंत्रण को अमल में लाने के उपाय लागू किए जाएं।	स्वीकृत। इस मद पर कार्यवाही जारी रहेगी।

दिनांक 29 नवम्बर 1971

संकल्प

सं० अनुभाग-II-72(1)/71—राजस्थान और गुजरात सरकारों के साथ सलाह करके यह फैसला किया गया है कि राजस्थान 2-371GI/71

राज्य में सभी संबंधित कार्यों समेत, माही बजाजसागर परियोजना के दक्ष, किफायती और शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक माही नियंत्रण बोर्ड स्थापित किया जाए। यह नियंत्रण बोर्ड, सभी तकनीकी एवं वित्तीय पहलुओं समेत, परियोजना का पूर्ण रूप से कार्यभारी होगा। वास्तविक निर्माण कार्य राजस्थान सरकार के सम्बन्ध मुख्य इंजीनियर द्वारा नियंत्रण बोर्ड के मार्गदर्शन में किया जाएगा।

2. दोनों राज्य सरकारों ने यह मान लिया है कि नियंत्रण बोर्ड के निर्देशन में निर्माण कार्य, सप्लाई और सेवाओं के लिए वे राजस्थान के मुख्य इंजीनियर को अधिकार दे दें, बहरहाल सभी कार्यों के सम्बन्ध में टेके राजस्थान सरकार के नाम पर निष्पादित होंगे।

3. दोनों राज्य सरकार यह भी स्वीकार करती हैं कि गुजरात सरकार द्वारा निर्माणाधीन माही कडाणा परियोजना के ऐसे पहलुओं के लिए भी नियंत्रण बोर्ड कार्य करेगा जो दोनों सरकारों को मान्य हों।

4. माही नियंत्रण बोर्ड में निम्नलिखित होंगे:—

1. सिंचाई और विद्युत् मंत्री, भारत सरकार। अध्यक्ष
2. सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री, भारत सरकार। सदस्य
3. माही बजाजसागर परियोजना का कार्यभारी मंत्री, राजस्थान सरकार। सदस्य
4. माही कडाणा परियोजना का कार्यभारी मंत्री, गुजरात सरकार। सदस्य
5. सचिव, सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय अथवा उनके द्वारा नामित कोई व्यक्ति। सदस्य
6. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) भारत सरकार अथवा उनका प्रतिनिधि। सदस्य
7. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति। सदस्य
8. मुख्य इंजीनियर, माही बजाजसागर परियोजना, राजस्थान सरकार। सदस्य
9. मुख्य इंजीनियर, माही कडाणा परियोजना, गुजरात सरकार। सदस्य
10. सचिव, वित्त विभाग (व्यय विभाग) राजस्थान सरकार। सदस्य
11. सचिव, वित्त विभाग, गुजरात सरकार। सदस्य
12. सचिव, सिंचाई और विद्युत् विभाग, राजस्थान सरकार। सदस्य

13. सचिव, सिचाई विभाग गुजरात सदस्य सरकार।

माही बजाजसागर परियोजना, राजस्थान, के कार्यभारी मंत्री और माही कडाणा परियोजना, गुजरात के कार्यभारी मंत्री बारी-बारी से, मंत्री, राजस्थान से आरम्भ करते हुए एक-एक वर्ष के लिए उपाध्यक्ष रहेंगे।

बोर्ड की सहायता के लिए एक सचिव, एक वित्तीय सलाहकार तथा यथावश्यक स्टाफ होगा।

बोर्ड का मुख्यालय बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

5. विशेष रूप में और उपर्युक्त पैरा 1 में दिए गए उपबंध की सामान्यता के प्रतिकूल न जाते हुए, माही नियंत्रण बोर्ड;

- (1) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए परियोजना-प्राक्कलन की जांच करेगा, आवश्यक संशोधनों के बारे में परामर्श देगा और राजस्थान सरकार की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए प्राक्कलन की सिफारिश करेगा;
- (2) अभिकल्पों को तैयार करने और विशेषज्ञों का परामर्श लेने के लिए सभी प्रस्तावों की जांच करेगा और उन पर अपना निर्णय देगा;
- (3) परियोजना के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए परियोजना के कार्यान्वयन में लगे मुख्य अभियंता, अधीक्षक, अभियन्ताओं, कार्यकारी अभियंताओं और उप-मंडलीय अधिकारियों के लिए, जैसा यह आवश्यक समझे, दोनों तकनीकी और वित्तीय अधिकारों के प्रत्या-योजन की समय-समय पर जांच करके उन्हें स्वीकृति प्रदान करेगा;
- (4) परियोजना के ठोस और दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए कार्यों की विभिन्न श्रेणियों के लिए दर अनुसूचियों की जांच करेगा और जहां आवश्यक हो वहां उनके लिए विशिष्टियां तैयार करेगा;
- (5) उन सभी उप-प्राक्कलनों और ठेकों को स्वीकृति देगा जिनकी लागत मुख्य इंजीनियर की स्वीकृति संबंधी शक्तियों से अधिक हो;
- (6) उन उप-प्राक्कलनों और ठेकों को तैयार करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा जो कि मुख्य इंजीनियर तथा अन्य परियोजना इंजीनियरों की स्वीकृति-शक्तियों के भीतर हों;
- (7) निश्चित दरों पर कार्य-आदेश के आधार पर नियत किए गए कार्यों और विस्तृत परिमाणगत प्राक्कलनों और सार्वजनिक निविदाओं पर आधारित कार्यों के अतिरिक्त, ठेके पर संभरणों अथवा कार्य के अधिनिर्णय के लिए सभी प्रस्तावों का अनुमोदन करेगा;

टिप्पणी (1)

जब किसी करार के अधीन कुल वित्तीय देनदारी को ठेके के प्रस्तुत किए जाने के समय ठीक-ठीक सुनिश्चित किया जा सकता हो और जब स्वयं ठेका ही निविदाओं के लिए किसी सार्वजनिक या सीमित 'मांग' के परिणामस्वरूप हो तो जब तक वह करार, अन्यथा, मुख्य इंजीनियर द्वारा मंजूरी के अधिकारों के अन्तर्गत आता हो प्रस्तावों को नियंत्रण बोर्ड के पहले से प्रस्तुत किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

टिप्पणी (2)

इससे मुख्य अभियंता अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं और उप-मंडलीय अधिकारियों को समय-समय पर दिये गये अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

- (8) अधिकारों के प्रत्यायोजन और अपने कारोबार को चलाने की क्रिया-विधि के संबंध में नियम बनायगा;
- (9) उपलब्ध धनराशि, परियोजना के आर्थिक पक्ष और परिणाम की शीघ्र प्राप्ति की वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए एक समन्वित तरीके से परियोजना के विभिन्न भागों के निर्माण का कार्यक्रम निश्चित करेगा;
- (10) बोर्ड द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए कार्यों के निर्माण और अन्य प्रयोजनों के लिए धन की आवश्यकताओं की जांच करेगा और दोनों राज्यों के बीच परियोजना की लागतों में उनके हिस्से के संबंध में हुए समझौते को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों को व्यय के बटवारे के संबंध में परामर्श देगा;
- (11) उपलब्ध जल के उत्तम उपयोग की प्राप्ति के उद्देश्य से जल और विद्युत् के चरणों में विकास और निर्माणावधि में जलाशय से सिचाई और बिजली के लिए जल की निकासी के संबंध में निश्चय करेगा;
- (12) माही बजाजसागर परियोजना के निर्माण-कार्यों के परिणामस्वरूप विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्यक्रम निश्चित करेगा, भूमि-उद्धार और विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसाने और उनके लिए पुनः घर बनवाने में हुए व्यय, जिसमें भू-अर्जन और इससे संबंधित खर्च सम्मिलित है, की जांच और अनुमोदन करेगा;
- (13) मुख्य अभियंताओं से एक निर्धारित फार्म में कार्य और व्यय दोनों के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्ट लेगा, परियोजना के विभिन्न यूनिटों की प्रगति का पुनरीक्षण करेगा और उस कार्य को शीघ्र कराने के लिए उठाये जाने वाले कदमों का निर्धारण करेगा

6. बोर्ड इसके कार्य-संचालन के नियम बनायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के अनेक मंत्रालयों, भारत के महा-नियंत्रक एवं लेखा-परीक्षक, प्रधान मंत्री के सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव और योजना आयोग को दे दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और राज्य सरकारों से यह निवेदन किया जाए कि वे इसे आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित करें।

बी० पी० पटेल, सचिव

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय**संकल्प**

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 1971

सं० एफ० सी० 3(16)/71—गंडक नदी में बारंबार ऊंची बाढ़ें आती रहती हैं, जिनसे उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर बरबादी होती है। गत 50 वर्षों के दौरान नदी के मार्ग में बहुत अधिक परिवर्तन आ गया है और यह पश्चिम की ओर हटने लगा है। नदी के और अधिक हटने पर रोक लगाने की दृष्टि से, नदी-नियंत्रण-निर्माण-कार्यों से समर्थित तटबंधों का समय-समय पर कार्यान्वयन किया जाता रहा है। इन उपायों पर अच्छी खासी रकम खर्च की जा चुकी है। अब तक किये गये उपायों के बावजूद नदी को उसकी वर्तमान स्थिति में रोक रखना मुश्किल साबित हो रहा है। इसलिए नदी के नियंत्रण के लिए किफायती और स्थायी उपाय निकालने हेतु इस समस्या का सावधानीपूर्वक विस्तृत अध्ययन किया जाना है। इस प्रयोजन से भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों के परामर्श से एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्णय किया है।

2. समिति में नीचे लिखे व्यक्ति होंगे:—

- | | |
|--|---------|
| 1. डा० ए० एन० खोसला | अध्यक्ष |
| 2. श्री पी० आर० गुहा, सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता, बिहार। | सदस्य |
| 3. श्री ए० सी० मित्र, सेवानिवृत्त अभियंताध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। | सदस्य |
| 4. श्री के० के० वर्मा, मुख्य अभियंता, सिंचाई, बिहार। | सदस्य |
| 5. श्री बी० आर० शोरी, मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय जल और विद्युत् आयोग। | सदस्य |
| 6. श्री सी० वी० गोले, निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना। | सदस्य |
| 7. श्री ओ० डी० शर्मा, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सिंचाई, उत्तर प्रदेश | सदस्य |

सचिव

3. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं:—

- (1) बचाव संबंधी और नदी-नियंत्रण कार्यों का निर्माण होने से पहले और बाद में गंडक नदी, भारत-नेपाल सीमा से लेकर गंगा के साथ उसका संगम होने तक, की स्थिति का अध्ययन।

- (2) उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर शुरू किये गये निर्माण कार्यों के निष्पादन का मूल्यांकन।

- (3) नियंत्रण ढांचों और तलछट-निष्कासन संबंधी उन निर्माण कार्यों सहित, जिन्हें नदी के प्रवाह को किसी अधिक मध्य सरणि के रूप में नियंत्रित करने के लिये अपनाया जा सकता है, विभिन्न प्रणालियों की जांच।

- (4) शुरू किये जाने वाले किफायती और स्थायी अतिरिक्त उपायों और पहले से क्रियान्वित निर्माण कार्यों के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के स्वरूप और सीमा के संबंध में सिफारिश करना।

4. समिति मई, 1972 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/रेल, वित्त, योजना, कृषि, परिवहन और विदेश मंत्रालयों/प्रधान मंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव/भारत के महा नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक को सूचनार्थ भेज दी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय और बिहार और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया जाय कि वे इसको आम जानकारी के लिए अपने राज्य के राजपत्रों में प्रकाशित करें।

एन० सी० सक्सेना, संयुक्त सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय**संकल्प**

नई दिल्ली दिनांक नवम्बर 1971

सं० 25017/1/70-एल II पतः, इस मंत्रालय के दिनांक 16/20 जनवरी 1971 के संकल्प संख्या जी०-250-17-1-70-एल-II के अनुसार भूमि तथा विकास कार्यालय की कार्यप्रणाली की विस्तृत जांच हेतु श्री होमी जे० एच० तेलयारखान, सदस्य, विधान सभा महाराष्ट्र की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

और जबकि, श्री होमी जे० एच० तेलयारखान के लिबिया में भारत के राजदूत नियुक्त होने के परिणाम स्वरूप, यह आवश्यक हो गया है कि उपरोक्त समिति का अध्यक्ष किसी और को नियुक्त किया जाये।

अतः अब अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष श्री अनिल के० चन्दा को श्री तेलयारखान के स्थान पर भूमि तथा विकास कार्यालय की कार्यप्रणाली की जांच के लिये पूर्वोक्त गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किया गया है।

यह भारत सरकार के राजपत्र में इस संकल्प की प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाये तथा इसे सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

(पी० सी० मैथ्यू, सचिव)

**श्रम और पुनर्वास मंत्रालय
(श्रम और रोजगार विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 29 नवम्बर 1971

सं० ब्यू०-16011(3)/71-डब्ल्यू० ई०—केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के नियमों और विनियमों के नियम 3(क) के अनुसरण में, भारत सरकार एतद्वारा श्री एन० पी० बुबे, संयुक्त सचिव, श्रम और पुनर्वास मंत्रालय को 26 नवम्बर, 1971 से श्री आई० डी० एन० साही, अपर सचिव, श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय के स्थान पर उक्त बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करती है।

2. तदनुसार, 20 दिसम्बर, 1958/29 अग्रहायण, 1880 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1, में प्रकाशित श्रम और रोजगार मंत्रालय की समय-समय पर यथा-सशोधित अधिसूचना सं० ई० एण्ड पी० 4(24)/58, तारीख 12 दिसम्बर, 1958 में निम्नलिखित परिवर्तन किए जाएंगे:—

वर्तमान प्रविष्टि, अर्थात्— भारत सरकार
“श्री आई० डी० एन० साही, द्वारा नामित
अपर सचिव,
श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय
नई दिल्ली।”

के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी:—

“1. श्री एन० पी० बुबे, भारत सरकार
संयुक्त सचिव, द्वारा नामित
श्रम और पुनर्वास मंत्रालय,
नई दिल्ली।”

हंस राज छाबड़ा, अपर सचिव

(रो० प्र० महानिदेशालय)

नई दिल्ली, दिनांक 2 दिसम्बर 1971

संकल्प

सं० ई० ई०-एफ/200/10/71—श्रम, रोजगार एवं पुनर्वास मंत्रालय, श्रम एवं रोजगार विभाग (रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय) के संकल्प संख्या एम० पी०-10(110)/69, दिनांक 19 दिसम्बर, 1970 में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को बेरोजगारी संबंधी विशेषज्ञ समिति का अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किया गया:—

1. श्री आर० के० सिन्हा, सदस्य, लोक सभा
2. श्री जे० एस० तिलक, सदस्य, राज्य सभा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र भाग एक अनुभाग एक में प्रकाशित किया जाए

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों के प्रशासनों तथा संबंधित अन्य सभी को भेजी जाए।

ईश्वर चन्द्र, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 27th November 1971

No. F. 3(23)-NS/68.—The President hereby makes the following rules further to amend the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 published with notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. F. 3(40)-NS/58, dated the 19th December, 1958, namely:—

1. (1) These rules may be called the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits)—Amendment Rules, 1971.
- (2) These rules shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the Post Office Savings Bank (Cumulative Time Deposits) Rules, 1959 the sub-rule 1(ii) of Rule 11 shall be amended to read as follows:—

“(ii) in the case of repayment in instalments, simple interest at 6% p.a. shall be calculated at the end of the period of repayment on the amount remaining unpaid at the end of each month from the month in which the withdrawal was made, and interest shall be recovered in one instalment either along with the last instalment of the repayment or in the month next following that month in which repayment of the last instalment was made.”

A. V. SRINIVASAN, Under Secy.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 24th November 1971

RESOLUTION

No. 11((2)/71/EEI.—Government of India had constituted a Panel for Steel Forgings Industry vide Resolution No. 11(1)/67-EI(M), dated 1st February, 1969 for a period of two years with a view to examine the various matters relating to the development of the Steel Forgings Industry. The previous term of the Panel has already expired on 31st January 1971, and it has now been decided to reconstitute the Panel for the Steel Forgings Industry.

2. The terms of reference of the Panel are:

- (a) Projection of demand typewise, sizewise, specification for the Fifth Five Year Plan;
- (b) Review of capacities, units already in production, gap if any, to be filled;
- (c) Diversification of existing units either to increase production or produce new range of production;
- (d) Assistance to be given for achieving the purposes mentioned in (b) and (c) above;
- (e) Problems, if any, regarding raw materials maintenance spares etc.;
- (f) Development of production machinery and equipment for this Industry as are not developed so far; to reduce the dependence on foreign exchange; and
- (g) Other matters of interest that may arise from time to time.

3. The Panel will consist of :

Chairman

- (i) Shri N. J. Kamath, Joint Secretary, Ministry of Industrial Development, New Delhi.

Members

- (ii) Shri V. P. Soni, Joint Director (Development) Railway Stores, Ministry of Railways (Railway Board) New Delhi.
- (iii) Shri P. R. Latey, Chief (Engineering), (Industry and Minerals Division) Planning Commission, New Delhi.
- (iv) Dr. A. K. De, Director, Central Mechanical Engineering Research Institute, Mahatma Gandhi Avenue, Durgapur-9.
- (v) Shri J. N. Luthra, Chief Technical Services, The National Industrial Development Corporation Ltd., Chanakya Bhavan, NDMC Complex, Vinay Marg, New Delhi.
- (vi) Shri K. P. Tandon, Chief Superintendent (Forge Shop), Heavy Engineering Corporation Ltd., Foundry Forge, P.O. Ranchi-4.
- (vii) Shri D. R. Malik, General Manager, Bharat Heavy Electricals Ltd., Ranipur (Hardwar) (U.P.).
- (viii) Shri N. Sen Roy, Chief Planning Officer, Joint Plant Committee, 18, Rabindra Sarani, Calcutta-1.
- (ix) Shri R. N. Dutta, General Manager, Ordnance Factory, Bhuswal.
- (x) Shri P. B. Jayakumar, Marketing Director (Engg.) & (Forging) Division, M/s. Guest, Keen, Williams Ltd., Jeevan Deep, 1, Middleton Street, Calcutta-16.
- (xi) Shri N. A. Kalyani, Director, M/s. Bharat Forge Co. Ltd., Mundhwa, Poona-1.
- (xii) Shri D. R. Sharda, Managing Partner, M/s. National Steel and General Mills, Patel Marg, Ghaziabad, (U.P.).

Member-Secretary

- (xiii) Shri V. V. Virabhadrayya, Development Officer, Directorate General of Technical Development, New Delhi.

4. This advisory Panel will meet to review the position once in six months and more frequently, if occasion warrants, at such places as may be decided by the Chairman. It will submit periodical reports to the Government of India about the matters handled by it.

5. The term of the Panel will be two years from the date of issue of this resolution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. C. SETHI, Dy. Secy.

DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS**(Company Law Board)**

New Delhi-1, the 1st December 1971

ORDER

No. 53/1/70-CL.II.—In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri Sooraj Kapoor, Accounts Officer, New Delhi, an Officer of the Government of India, Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209.

2. The Company Law Board hereby revokes the authorisation earlier issued in favour of Shri Sooraj Kapoor in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade & Company Affairs, Department of Company Affairs Order No. 51/1/65-CL.II, dated the 18th July, 1969.

K. D. GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING**(Department of Family Planning)**

New Delhi, the 19th November 1971

RESOLUTION

No. F.2-11/71-Ply.—The Central Family Planning Council at its meeting held at Jaipur in October 1971, recommended that an Executive Committee of the Council be constituted for dealing with various matters which arise from time to time in the Family Planning Programme in the interregnum between the meetings of the Council. The Government of India have accepted this recommendation and resolve that an Executive Committee of the Council be constituted with the following composition :—

Chairman

Union Minister of Health and Family Planning.

Vice-Chairman

Union Minister of State for Health and Family Planning.

Deputy Chairman

Deputy Minister for Health and Family Planning.

Members

Minister for Health, Orissa.
Minister for Health, Maharashtra.
Minister for Health, Tamil Nadu.
Minister of State for Health, Uttar Pradesh.

Convener

Member-Secretary, Central Family Planning Council.

2. The Executive Committee may be entrusted with such tasks as may be assigned to it by the Chairman from time to time and assist the Chairman in all matters pertaining to the Council.

3. The Executive Committee will meet at such time and place as may be decided by the Chairman.

4. The tenure of the Committee will be co-terminus with the tenure of the present Council.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

The 2nd December 1971

RESOLUTION

No. 17-15/71-AP(Ply).—The Government of India are pleased to constitute a "Coordination Committee for Research in Family Planning" to coordinate research in the fields of reproductive, biology, demography and communication action.

The composition of the Committee will be as under :—

Chairman

1. Secretary, Ministry of Health and Family Planning.

Members

2. Joint Secretary, Family Planning.
3. Director General of Health Services.
4. Director General of Indian Council of Medical Research.
5. Commissioner, Family Planning.
6. Director, National Institute of Family Planning, New Delhi.
7. Dr. M. K. Krishna Menon, Gynaecologist, Madras.
8. Dr. N. R. N. Prasad, Department of Zoology, University of Delhi, Delhi.
9. Dr. V. Ramalingaswamy, Director, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.
10. Dr. M. L. Dhar, Director, Central Drug Research Institute, Lucknow.
11. Dr. D. N. Pai, Department of Preventive and Social Medicine, Topiwala National Medical College, Bombay.

Member-Secretary

12. Deputy Commissioner (Training and Research) Department of Family Planning.

3. The terms of reference of the Committee will be :—

1. to define goals and suggest priorities for research in the field of reproductive biology, demography and communication action in relation to family planning,
 2. to coordinate research activities in the foregoing fields,
 3. to identify areas of research and approve institutions where research activity should be undertaken, and
 4. to evaluate the progress of research from time to time.
4. The Committee shall have the power to coopt/invite other experts to attend its meetings and to set up sub-committees as it may consider necessary. The Committee may meet as often as necessary. Normally the meetings of the committee shall be held in New Delhi.

5. The life of the Committee shall be two years.

6. Non-official members and invitees to the Committee shall be entitled to the grant of travelling and daily allowances for attending meetings of the Committee at the rates admissible to an officer of the highest grade in Class I of the Central Services. Members of the Committee who are Government servants will draw travelling and daily allowances as admissible to them from the same source from which they get their salary.

7. The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under major head 30-A Family Planning, C(1) Technical advice and Supervision under Demand No. 37 Medical and Public Health for 1971-72.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

R. N. MADHOK, Jt. Secy.

MINISTRY OF TOURISM & CIVIL AVIATION

(Department of Tourism)

New Delhi, the 30th November 1971

RESOLUTION

No. 5-T.Coord(4)/70.—In the Government of India, Ministry of Tourism & Civil Aviation, Department of Tourism regarding the reconstitution of the Tourist Development Council.

Resolution No. 3-TT(14)/57, dated 27th February, 1958 in the Government of India, Ministry of Transport & Communications, Department of Transport, as amended by the Government of India Resolutions bearing the same number dated the 23rd April, 1958; 24th July, 1958 and 26th December 1958 No. 3-TPL.II(7)/62, dated the 31st July, 1962 and No. 8-TH(3)/64, dated the 25th June, 1964, No. 13-TPL. I(5)/64, dated the 2nd August, 1965, No. 13-TPL.I(5)/64, dated the 10th June 1966 and the Ministry of Tourism and Civil Aviation, Department of Tourism Resolution No. 13-TPL.I(2)/67, dated the 7th June, 1967; No. 13-TPL.I(2)/67, dated the 3rd July, 1968 and No. 13-TPL.I(2)/67, dated 13th August, 1968, the existing part III of the Resolution will be amended to read as follows :

III. Composition of the Council

The Constitution of the Council shall be as follows :

Chairman

- (i) Minister of Tourism & Civil Aviation in the Central Government.

Vice-Chairman

- (ii) Minister of State for Tourism & Civil Aviation in the Central Government.

1. Member (Industry), Planning Commission.
2. Ministers in charge of Tourism in each State and Union Territory of Goa (19 States including Meghalaya and one Union Territory with legislature).
3. The Chief Executive Councillor, Delhi Administration, Delhi.
4. Secretary, Ministry of Tourism & Civil Aviation.

5. Director-General, Department of Tourism.
6. Director-General, Department of Civil Aviation.
7. Director-General, Archaeological Survey of India.
8. Inspector General of Forests, (Ministry of Food and Agriculture).
9. One representative of the Ministry of Finance, Department of Expenditure.
10. One representative of the Ministry of Works, Housing and Supply.
11. One representative of the Ministry of Railways.
12. One representative of the Ministry of Transport and Shipping.
13. Minister in charge of Tourism/Chief Secretary of a Union Territory (not permanently represented).
14. Nine (9) Members of Parliament. They shall be nominated by the Government of India in the Ministry dealing with Tourism.
15. One representative of the Federation of Hotel and Restaurant Associations of India.
16. One representative of the Travel Agents Association of India.
17. One representative of the Shikar Outfitters Association of India.
18. One representative of Air India.
19. One representative of Indian Airlines.
20. One representative of the Indian Tourism Development Corporation Ltd.
21. One representative of the Federation of Automobile Associations of India.
22. One representative of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.
23. Nine Members of the Public to be nominated by the Ministry of Tourism & Civil Aviation.

Secretary

An official nominated by Central Government shall be the Secretary of the Council.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

B. N. RAMAN, Director-General, Tourism &
Ex-Officio, Jt. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION & POWER

New Delhi, the 27th November 1971

RESOLUTION

No. 12(1)/70-Mat.—The Government of India in the Ministry of Irrigation & Power constituted on 8th July, 1969 a Committee of Ministers under the Chairmanship of Shri Kamalapati Tripathi, the then Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, to go into the causes for delays in procurement of construction equipment and spare parts required for Irrigation & Power Projects and to suggest measures for elimination of delays in procurement.

2. On Shri Kamalapati Tripathi's laying down the Office of the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh, Prof. Siddheshwar Prasad, Union Deputy Minister for Irrigation & Power, was requested to convene the meetings of the Committee.

3. The Committee submitted its Report to the Government of India in the Ministry of Irrigation & Power on 6th July, 1970. This report was considered and Committee's recommendations accepted by the 5th Conference of the State Ministers of Irrigation & Power held at Ootacamund on 24th & 25th September, 1970.

4. The recommendations of the Committee and the decisions of the Government of India thereon are set out in the Annexure.

5. The Government wish to place on record their appreciation of the valuable work done by the Committee.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B. P. PATEL, Secy.

ANNEXURE

S. No.	Recommendation of the Committee	Decision of the Government
1.	The concession available to the Priority Industries in the Import Trade Control Policy for importing restricted spare parts up to the prescribed limits, without obtaining DGTD clearance, should also be applicable to Irrigation & Power Projects and State Electricity Boards.	Accepted. Necessary Provision has been incorporated <i>vide</i> para 204 in the Import Trade Control Hand Book of Rules & Procedure 1971.
2.	The emergency licences for importing emergency spares to overcome breakdown of production machinery should be allowed to the Irrigation & Power Projects. The value of such licences during a licensing period should be fixed at 0.1% of the value of the equipment in hand with each project.	Accepted. Emergency licences up to 0.1% of the value of equipment in hand with each Irrigation Project and State Electricity Board/Power Project/Undertakings would be permitted subject to fixation of ceilings for each Project/Board to be notified by the Ministry of Irrigation & Power from time to time. As a further facility, the Irrigation Projects and Electricity Boards/Power Projects and Undertakings will approach Regional Licensing Authorities concerned for issue of Emergency Licences.
3.	There should be no advertisement in the Indian Trade Journal for <i>restricted items</i> . In respect of non-restricted items, the condition of advertisement may be relaxed in the case of Actual Users.	Accepted in respect of Actual Users. For established importers of spares for earthmoving machinery the advertisement procedure will continue to be applicable.
4.	In case of foreign exchange releases for Irrigation & Power Projects under Loans/Credits, the terminal dates of loans and the delivery period should be indicated on the letters of sanction releasing foreign exchange to enable CCIE to revalidate licences without reference to the concerned departments.	Accepted. The terminal dates of loans and delivery period would be incorporated in the foreign exchange sanctions, given to Irrigation and Power Projects and State Electricity Board's/Undertakings under Project Loans.
5.	Steps should be taken to minimise procedural delays in processing requisitions for import of equipment and spare parts; new application forms should be devised combining the form for release of foreign exchange and the form for issue of Import Licence; time taken for processing the import licence applications should be limited to one month.	Accepted. Simplified procedure and new combined form for release of foreign exchange and issue of Import Licence for import of spares have been devised and circulated to all the Irrigation & Power Projects/ Electricity Boards and Undertakings by the Ministry of Irrigation & Power.
6.	DGS&D rate contracts for import of spare parts should be finalised in good time before the period of validity of the previous rate contracts expires.	Accepted.
7.	DGS&D should cover more and more items by Rate Contracts for indigenous spare parts. DGS&D should also cover the indigenously manufactured items of equipment under DGS&D Rate Contracts.	Accepted.
8.	A Committee should be constituted by DGTD to review cases of import of equipment, components and accessories which require special consideration. The Committee should meet once a month.	Accepted. A meeting would be held in the DGTD each month to review pending cases of Irrigation & Pwer Projects/ Electricity Boards and Undertakings requiring indigenous clearance.
9.	DGTD should compile and publish lists of items of spare parts and equipment which are being manufactured indigenously.	Accepted
10.	Bulk allocation of foreign exchange be made in favour of dealers of equipment/established importers of spare parts on sustained basis for importing such spare parts as may serve to supplement the available stocks of spare with Users and as may not be readily available with the users. Simultaneously bulk allocation of foreign exchange should be continued to be made to the Ministry of Irrigation & Power to meet the requirement of Actual Users.	Accepted
11.	Setting up of Central Mechanical Unit Organisation at State levels and strengthening the existing ones to guide the project authorities in the matter of proper utilisation of equipment, rehabilitation of surplus machines and inventory control of spare parts.	Accepted. State Governments have been requested to ensure implementation.
12.	A Construction Plant & Machinery Committee be constituted to compile statistical data regarding population of construction equipment in the country and to lay down norms regarding productivity of different items of equipment, unit cost of work with different machines, and standardisation of equipment. The Mechanical Organisation of the CW&PC should be suitably strengthened so that an officer of a suitable status can finalise necessary schemes/measures for effective implementation.	Accepted. A committee has been set up to enquire and report on the optimum utilisation of equipment imported in the country.
13.	The DGTD, the CW&PC and the DGS&D should examine the extent of increasing import substitution, production of indigenous spares and the price structure of indigenously manufactured equipment and spare parts.	Accepted. This is an item of continuing action.
14.	Measures should be enforced to exercise strict inventory control on stocks of spare parts for Earthmoving Machines etc.	Accepted. This is an item of continuing action .

RESOLUTION

New Delhi, the 27th November 1971

No. DW.11-72(1)/71.—In consultation with the Government of Rajasthan and Gujarat, it has been decided to set up a Mahi Control Board with a view to ensuring the efficient, economical and early execution of the Mahi Bajajisagar Project, including all connected works in the State of Rajasthan. The Control Board will be in overall charge of the project including its technical and financial aspects. The actual works of construction will be carried out under the direction of the Control Board by the Chief Engineer concerned of the Rajasthan Government.

2. The two State Governments agree to delegate powers to the Chief Engineer, Rajasthan, to contract for works, supplies and services under the direction of the Control Board; the contracts in respect of all works will however be executed in the name of Government of Rajasthan.

3. The two State Governments further agree that the Control Board's functions may be extended to cover such aspects of Mahi Kadana Project under construction by the Government of Gujarat as may be agreed to by the two Governments.

4. The Mahi Control Board will consist of the following :

Chairman

- (i) Minister of Irrigation and Power Government of India.

Members

- (ii) Deputy Minister, Ministry of Irrigation and Power, Government of India.
- (iii) Minister in charge of Mahi Bajajisagar Project, Rajasthan Government.
- (iv) Minister in charge of Mahi Kadana Project, Gujarat Government.
- (v) Secretary, Ministry of Irrigation and Power or his nominee.
- (vi) Joint Secretary, Ministry of Finance (Department of Expenditure) Government of India, or his representative.
- (vii) Chairman, Central Water and Power Commission, or alternate nominated by him.
- (viii) Chief Engineer, Mahi Bajajisagar Project, Rajasthan Government.
- (ix) Chief Engineer, Mahi Kadana Project Gujarat Government.
- (x) Secretary, Finance Department (Expenditure) Government of Rajasthan.
- (xi) Secretary, Finance Department, Government of Gujarat.
- (xii) Secretary, Irrigation and Power Department, Government of Rajasthan.
- (xiii) Secretary, Irrigation Department, Government of Gujarat.

The Minister in charge of Mahi Bajajisagar Project, Rajasthan and Minister in charge of Mahi Kadana Project, Gujarat will be Vice-Chairman for one year each by rotation commencing with the Minister, Rajasthan.

The Board will be assisted by a Secretary, a Financial Adviser and such other staff as may be necessary.

The headquarters of the Board will be fixed by the Board.

5. In particular and without prejudice to the generality of the provision in paragraph 1 above, the Mahi Control Board shall :—

- (i) Scrutinize the estimate of the Project prepared by the Rajasthan State Government, advise necessary modifications and recommend the estimate for administrative approval of the Rajasthan Government;
- (ii) examine and decide all proposals for preparation of designs and for obtaining expert advice;
- (iii) examine and approve from time to time the delegation of such powers, both technical and financial, as it may deem necessary for the efficient execution of the project, to the Chief Engineer, Superintending

Engineers, Executive Engineers and Sub-divisional Officers engaged in the execution of the Project;

- (iv) examine and, where necessary, lay down specification and schedule of rates for various classes of work with a view to sound and efficient execution of the Project;
- (v) approve all sub-estimates and contracts, the cost of which exceeds the powers of sanction of the Chief Engineer.
- (vi) laydown guidelines for the preparation of sub-estimates and contracts which may be within the power of sanction of the Chief Engineer & other project engineers.
- (vii) approve all proposals for award of work or supplies on contract other than those based on public tenders and on detailed quantitative estimates and works allotted on work order basis on schedule rates;

NOTE (1)

Where total financial liability under a contract is definitely ascertainable at the time of placing the contract and where the contract itself is the result of a public or limited call for tenders, prior, submission of the proposals to the Control Board will not be necessary so long as the contract is otherwise within the powers of sanction of Chief Engineer.

NOTE (2)

This will not affect the powers delegated from time to time to the Chief Engineer, Superintending Engineers, Executive Engineers and Sub-divisional Officers.

- (viii) frame rules as to delegation of powers and procedure for the purpose of carrying out its business,
- (ix) decide the programme of construction of different parts of the Project in a coordinated manner keeping in view the funds available, the economics of the Project and the desirability of obtaining quick result;
- (x) examine the requirements of funds for the construction of works and other purposes for the execution of the project according to the programme laid down by the Board and advise the apportionment of the expenditure to the two States, keeping in view the agreement between the States on the sharing of costs of the project.
- (xi) decide on the stage development of water and power and the withdrawals of water from the reservoir during the construction period for irrigation and power purposes with a view to securing best use of water available
- (xii) decide the programme of resettlement of persons displaced as a result of the Mahi Bajajisagar Project works, scrutinize and approve the estimates of land reclamation and the expenditure incurred in resettlement and rehousing of the displaced persons including land acquisition and connected charges;
- (xiii) receive monthly progress reports both as to works and expenditure in a prescribed form from the Chief Engineers, review the progress of different units of the Project and lay down steps to be taken to expedite the work.

6. The Board will frame its Rules of Business.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all the State Governments, the several Ministries of the Government of India, the Comptroller and Auditor General of India, Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President and Planning Commission.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

B. P. PATEL, Secy.

New Delhi, the 29th November 1971

No. FC.3(16)/71.—High floods frequently occur in the Gandak River causing large scale devastation in Uttar Pradesh and Bihar. The course of the river has altered considerably

in the last 50 years and it has showed a tendency to move westwards. In order to check further movement of the river, embankments, supported with river training works, have been implemented from time to time. Considerable amount has been spent on these measures. In spite of the measures taken so far, it is proving difficult to hold the river in its present position. A careful study of the problem has, therefore, to be made in detail to evolve economical and permanent measures for the control of the river. For this purpose, the Government of India in consultation with the State Governments of Uttar Pradesh and Bihar, have decided to set up a High level Committee.

2. The Committee will consist of :—

Chairman

1. Dr. A. N. Khosla,

Members

2. Shri P. R. Guha, Retd. Chief Engineer, Bihar.

3. Shri A. C. Mitra, Retd. Engineer-in-Chief, Uttar Pradesh.

4. Shri K. K. Verma, Chief Engineer, Irrigation, Bihar.

5. Shri B. R. Shori, Chief Engineer, Central Water and Power Commission.

6. Shri C. V. Gole, Director, Central, Water and Power Research Station, Poona.

Member-Secretary

7. Shri O. D. Sharma, Addl. Chief Engineer, Irrigation, Uttar Pradesh.

3. The terms of reference of the Committee are :—

(i) To study the behaviour of the river Gandak from Indo-Nepal border to its confluence with the Ganga before and after the construction of protective and river training works.

(ii) To evaluate the performance of the works undertaken by Uttar Pradesh and Bihar State Governments from time to time.

(iii) To examine different methods including construction of control structures and dredging which can be adopted to train the river flow in a more central channel.

(iv) To recommend economical and permanent additional measures that are to be taken and nature and extent of remodelling and strengthening of works already executed.

4. The Committee will submit their report by the end of May, 1972.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Governments of Bihar and Uttar Pradesh, Ministries of Railways, Finance, Planning, Agriculture, Transport and External Affairs/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Governments of Bihar and Uttar Pradesh be requested to publish it in the State Gazettes for general information.

N. C. SAKSENA, Jt. Secy.

MINISTRY OF WORKS & HOUSING

RESOLUTION

New Delhi, the 1st December 1971

No. G-25017/1/70-LII.—WHEREAS in this Ministry's Resolution No. G-25017/1/70-LII, dated the 16th/20th January, 1971, a Committee was constituted under the Chairmanship

of Shri Homi J. H. Taleyarkhan, Member, Legislative assembly, Maharashtra, to investigate comprehensively the working of the Land and Development Office;

AND WHEREAS, consequent upon the appointment of Shri Homi J. H. Taleyarkhan as Ambassador of India to Libya, it has become necessary to appoint someone else as Chairman of the aforesaid Committee;

NOW, THEREFORE, it has been decided to appoint Shri Anil K. Chanda, Chairman, all India handicrafts Board, as the Chairman of the aforesaid Committee constituted to investigate the working of the Land and Development Office, in place of Shri Taleyarkhan.

This will take effect from the date of publication of this Resolution in the Gazette of India.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

P. C. MATHEW, Secy.

MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION

(Department of Labour and Employment)

New Delhi, the 29th November 1971

No. Q-16011(3)/71-WE.—In pursuance of Rule 3(a) of the Rules and Regulations of the Central Board for Workers' Education, the Government of India hereby nominates Shri N. P. Dube, Joint Secretary, Ministry of Labour and Rehabilitation as Chairman of the said Board with effect from the 26th November, 1971, *vice* Shri I. D. N. Sahi, Additional Secretary, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation.

2. The following changes shall accordingly be made in the Ministry of Labour & Employment Notification No. E&P 4(24)/58 dated the 12th December, 1958, published in the Gazette of India Part I Section I dated December 20, 1958/ Agrhayana 29, 1880, as amended from time to time :—

For the existing entry viz.

"1. Shri I. D. N. Sahi, Additional Secretary, Ministry of Labour, Employment & Rehabilitation, New Delhi."—

Nominated by the Government of India.

the following shall be substituted :—

"1. Shri N. P. Dube, Joint Secretary, Ministry of Labour & Rehabilitation, New Delhi,"—Nominated by the Government of India.

HANS RAJ CHHABRA, Under Secy.

D.G.E. & T.

New Delhi, the 2nd December 1971

RESOLUTION

No. EEI/200/10/71.—In partial modification of the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment (Directorate General of Employment and Training) Resolution No. MP-10(110)/69, dated the 19th December, 1970, the following are appointed as additional members of the Expert Committee on Unemployment :

1. Shri R. K. Sinha, Member, Lok Sabha.

2. Shri J. S. Tilak, Member, Rajya Sabha.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India-Part I Section I.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned.

ISHWAR CHANDRA, Jt. Secy.

